हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

01 फरवरी 2026, समय 1305

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में लगातार अपना 9वां बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा - बजट, आर्थिक वृद्धि आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ, सबका विकास की परिकल्पना के तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। इससे प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र को संसाधन, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने इसे क्षमता निर्माण और सुधारों पर बल देने वाला और इसे युवा शक्ति से संचालित बजट बताया। बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई प्रस्ताव किए गए, जिनमें खादी हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, वस्त्र क्षेत्र के लिए बजट में राष्ट्रीय फाइबर योजना और राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम को बढ़ावा के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना शामिल है। वित्त मंत्री ने दस हजार करोड़ रुपए की लघु और मध्यम उद्यम – एस.एम.ई विकास कोष की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे इस क्षेत्र के भविष्य के चैंपियन उभरेंगे। श्रीमती सीतारामन ने कहा- एस एम ई ऋण लेने वालों के लिए अव-संरचना जोखिम गारंटी कोष की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा अगले पांच वर्ष के लिए बायो-फार्मा शक्ति के लिए दस हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने तीन नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने और वर्तमान सात संस्थानों को उन्नत करने की घोषणा की। श्रीमती निर्मला सीतारामन ने इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना के लिए चालीस हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी किया। बजट में अगले पांच वर्षों में कंटेनर विनिर्माण योजना के लिए दस हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति का प्रस्ताव है। बजट में दिए गए अन्य प्रस्तावों की बात करें तो खनन प्रसंस्करण अनुसंधान और विनिर्माण के लिए तीन समर्पित रासायनिक पार्क की स्थापना की जाएगी। पांच लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत व्यय की सीमा 12 लाख बीस हजार करोड़ रुपए तक बढ़ाई गई। बजट में पूर्व में दानकुनी से सूरत तक नए समर्पित माल गलियारे की स्थापना की घोषणा की गई है। अगले पांच वर्ष में बीस नए राष्ट्रीय जलमार्ग संचालित होंगे, इससे ओडिशा में खनिज समृद्ध तलचर और अंगुल आपस में जुड़ जाएंगे। वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जहाज मरम्मत व्यवस्था स्थापित की जाएगी। रेल और सड़क यातायात पर बोझ कम करने के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। अगले पांच वर्ष में विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन

और रासायनिक उपकरणों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बीस हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी किया गया है। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

****

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट में लाभांश और म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाली आय पर ब्याज न काटने की घोषणा की है। भारत से बाहर रहने वाले लोगों को सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में निवेश की अनुमति दी गई है। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा के लिए विकसित भारत बैंकिंग उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है। बजट में आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। संशोधित आयकर रिटर्न और देरी से भरे गए आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ाई गई है, संशोधित आयकर रिटर्न 31 मार्च तक भरा जा सकेगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी।

****

केंद्र सरकार विकसित भारत के प्रमुख संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए उच्च-स्तरीय शिक्षा से रोजगार और उद्योग स्थाई समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, सरकार अखिल भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान को प्रोत्साहन देगी। मुंबई में 15 हजार माध्यमिक स्कूलों और पांच सौ कॉलेजों में एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, और कॉमिक्स का कंटेंट तैयार करने वाली ए.वी.सी.जी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा- बड़े उद्योगों और लॉजिस्टिक कॉरिडोर को सहायता प्रदान करने के लिए पांच टाउनशिप विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।

****